4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

वर्ष : 02- अंक : 21 - दिसंबर 2024

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

सर्व सहकार सर्व साकार

सहकार उदय

वैश्विक स्तर पर सहकार से समृद्धि की गूंज

भारतीय सहकारिता के क्रांतिकारी सुधारों को दुनिया ने सराहा

2025
अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत : प्रधानमंत्री 18

24 सहकारी डेयरी आंदोलन से महिलाएं बनीं सशक्त और गांव हुए समृद्ध

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 1/32

अनुक्रमणिका

सहकार उदय

दिसंबर 2024, अंक 21, वर्ष 02

संपादक मंडल

प्रधान संपादक

संतोष कुमार शुक्ला

संपादक

रोहित कुमार

सह संपादक

अँक अँजलीदीप

सदस्य

माधवी एम. विप्रदास

विवेक सक्सेना

हितेंद्र प्रताप सिंह

राशिद आलम

सहकार उदय से जुड़ी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलेख देना चाहते है तो हमें ई-मेल करें:
प्रकाशन का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

sahkaruday@iffco.in

महाप्रबंधक (सहकारिता विकास)
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर
साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017

इफको से जुड़ने के अन्य पते:

Iffco.coop

IFFCO_PR

Iffco_coop

प्रकाशक-इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड
मुद्रक-रॉयल प्रेस, बी-81, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

वैश्विक स्तर पर सहकार से समृद्धि की गूंज भारतीय सहकारिता के क्रांतिकारी सुधारों को दुनिया ने सराहा

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन और आईसीए की महासभा की बैठक में भारतीय सहकारिता की गूंज रही। दुनियाभर से आये सहकारी नेताओं और सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की सहकारिता से लोगों के जीवन स्तर में आए क्रांतिकारी सुधार को जमकर सराहा।

आवरण कथा

पेज 06 देखें

पेज 14 देखें

सहकारी समितियों को एकीकृत करने में राष्ट्रीय डेटाबेस की अहम भूमिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है।

पेज 15 देखें

सरकार ने डिजिटल क्रांति के माध्यम से बनाया न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के समग्र विकास और देशवासियों के हितों की रक्षा की दिशा में बहुआयामी कदम बढ़ा रही है।

पेज 16 देखें

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका

पेज 18 देखें

वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत : प्रधानमंत्री

पेज 22 देखें

गांवों की तरक्की में जिला सहकारी बैंकों की अहम भूमिका- श्री अमित शाह

पेज 25 देखें

श्वेत क्रांति के जनक- डॉ वर्गीज कुरियन

पेज 20 देखें

धर्मांतरण विरोधी आंदोलन के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा देश

पेज 27 देखें

सहकारिता सम्मेलन में पहुंचे जाने माने वैश्विक सहकारी नेता

4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

वैश्विक सम्मेलन से सशक्त हुई सहकारिता

नवंबर 2024 में भारत ने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का भव्य आयोजन कर विश्व में सहकारिता आंदोलन में अपनी भूमिका को सशक्त किया है। सहकारिता के इस महाकुंभ में दुनिया के लगभग 100 देशों ने भाग लिया। 1500 विदेशी मेहमानों के साथ सहकारिता सम्मेलन में 3000 से अधिक सहकारी नीति निर्माताओं और सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और इफको के विशेष सहयोग से देश में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस सम्मेलन की काफी सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प से प्रेरित थीम 'सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार' को एक आदर्श रूप में लेते हुए वैश्विक सम्मेलन के दौरान इस पर विशेष चर्चा की गई कि किस प्रकार सहकारिताएं सभी के लिए समृद्धि का निर्माण कर सकती हैं। सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) की महत्वपूर्ण महासभा के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहायक नीतियों को सक्षम बनाना, मजबूत नेतृत्व का विकास और एक स्थाई भविष्य का निर्माण करना आदि विषयों पर वैश्विक चर्चाओं का आयोजन किया गया। इसके ठोस एवं बेहतरीन परिणामों से सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा मिलेगी। वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का शुभारंभ दुनिया के दिग्गज सहकारी संगठन, नीति निर्माता एवं सदस्यों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सहकारिता को वैश्विक सहकारी सम्मेलन से महत्वपूर्ण दृष्टि मिलेगी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का औपचारिक शुभारंभ भी किया, जिसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया, जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रतीक है। इस छह दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन पूर्णतः भारतीय संस्कृति के अनुरूप किया गया। जिसमें शुद्ध शाकाहारी भोजन, भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही पीपल के 10000 पौधों को लगाना शामिल किया गया।

सम्मेलन के दौरान भारतीय सहकारिता के लिए गौरवपूर्ण क्षण उस समय आया, जब इफको के प्रबंध निदेशक डॉ उदय शंकर अवस्थी को उनके विशिष्ट योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानि आईसीए द्वारा सहकारिता जगत का सर्वोच्च सम्मान रोशडेल पायनियर्स अवार्ड दिया गया। यह सम्मान भारत की सहकारी सफलता को वैश्विक मंच पर मान्यता प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने पर सहकार उदय पत्रिका की टीम इफको के प्रबंध निदेशक को हार्दिक बधाई प्रेषित करती है।

सहकार उदय के इस अंक में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन पर विस्तृत आलेखों के साथ ही अन्य ज्ञानवर्धक और रोचक विषयों को शामिल किया गया है, इमे विश्वास है कि पत्रिका का यह अंक भी आपके लिए प्रेरणादायक और उपयोगी साबित होगा। ■

सादर धन्यवाद

जय सहकार

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 3/32

भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर किया है। भारत अपने विकास में आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल देखता है। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियों को बहुद्देशीय बनाया जाए। हम *सहकार से समृद्धि* के मंत्र पर चल रहे हैं और सरकार व सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ग्रामीण सहकारी बैंक गांवों की आर्थिक प्रगति के आधार हैं। भारत सरकार इन बैंकों को सशक्त कर हर किसान और ग्रामीण को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। सहकारी बैंक ऋण वितरण योजनाओं, डोर-स्टेप बैंकिंग, किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं से संपन्न होकर ग्रामीण अर्थतंत्र के सशक्तिकरण में योगदान देते रहेंगे।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से ग्रामीण विकास में पैक्स की भूमिका बढ़ रही है। पैक्स के कार्यों में विविधता आ रही है। पैक्स अब पीएम जन औषधि केंद्र, पीएम किसान समृद्धि केंद्र एवं कार्यों के साथ-साथ कई गांवों में पानी समितियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे उनकी आय के स्रोत बढ़ रहे हैं।

श्री मुरलीधर मोहोल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

सहकारिता के माध्यम से ही विश्व में शातिपूर्ण और रक्तहीन क्रांति संभव है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन भारत में होना राष्ट्रीय गौरव की बात है।

श्री दिलीप संघाणी
अध्यक्ष, एनसीयूआई एवं इफको

इफको के नैनो उत्पाद, जैसे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी किसानों को बेहतर फसल पैदावार प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन उत्पादों का भंडारण और परिवहन आसान है। किसी भी फसल पर इनका छिड़काव किया जा सकता है।

डॉ. उदय शंकर अवस्थी, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इफको

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आयोजन सहकारिता के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करने में मदद करेगा। इससे विभिन्न देशों के बीच अनुभव और सर्वोतम प्रथाओं का आदान-प्रदान होगा, जिससे भारत में सहकारी संस्थाओं को और मजबूती मिलेगी।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और मिलैट्स व सहकारिता वर्ष से

भारत की बढ़ी वैश्विक साख

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की विभिन्न पहलों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। पिछले एक दशक में तीन प्रमुख विषयों योग, मिलैट्स (श्रीअन्न) और सहकारिता को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों की चौतरफा प्रशंसा हो रही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से जहां विश्व स्तर पर भारत की योग पद्धति से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, वहीं भारत के साथ दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। मिलैट्स वर्ष से श्रीअन्न का वैश्विक महत्व बढ़ा है और इससे भारतीय किसानों को प्रोत्साहन मिला है। स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के इन पोषक अनाजों के प्रति बढ़ते आकर्षण से किसानों को श्रीअन्न का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा से पूरी दुनिया में भारतीय सहकारिता की विश्वसनीयता को बल मिला है।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। उस समय वैश्विक स्तर पर योग दिवस मनाने के भारतीय प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में 177 देशों ने सहमति जताई और दुनिया के देशों के भारी समर्थन के साथ 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 21 जून 2015 को पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया के लगभग 84 देशों में इसे भारी उत्साह के साथ भागीदारी की। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर भारत के सुझाव पर वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलैट्स वर्ष के रूप में मनाया गया। कृषि व खाद्य संगठन (एफएओ) ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। भारत में श्री अन्न वर्ग के अनाज की सर्वाधिक खेती होती है। स्वास्थ्य के मद्देनजर मोटे अनाज (श्रीअन्न) की मांग पूरी दुनिया में है। इस वर्ग वाली फसलों की खेती सीमित प्राकृतिक संसाधनों में हो सकती है। इसी को देखते हुए भारत में इसकी खेती को पूरा प्रोत्साहन मिला है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मोटे अनाज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृषि से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और निर्यातकों के बीच समन्वय स्थापित कर इसे आगे बढ़ाया गया।

अंतरराष्ट्रीय मिलैट्स वर्ष 2023 के दौरान पूरा फोकस उत्पादन और उत्पादकता, उपभोग, निर्यात, मूल्य शृंखला को मजबूत बनाने, ब्रांडिंग, स्वास्थ्य लाभ जागरूकता बढ़ाने पर रहा। सरकार ने इसे जन-अभियान बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि भारतीय मोटे अनाजों, उनके व्यंजनों, मूल्य वर्धित उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। भारत में मिलैट्स पाक-कला उत्सव, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, शेफ सम्मेलन, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), रोड़ शो, किसान मेलों, अर्धसैनिक बलों के लिए रसोइया प्रशिक्षण, दिल्ली और इंडोनेशिया में आसियान भारत मिलेट त्योहार आदि में श्रीअन्न (मिलेट) को बढ़ावा दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की घोषणा के साथ पूरी दुनिया में सहकारिता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। नई दिल्ली में छः दिवसीय वैश्विक सहकारिता सम्मेलन के आयोजन से सहकारी आंदोलन को नई दिशा मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस पहल को भारत में हाथोंहाथ लिया गया। आगामी वर्ष 2025 में सहकारी आंदोलन के माध्यम से गरीब, वंचित, महिला और युवाओं को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्रालय ने पूरे वर्ष सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के साथ लोगों को इससे जोड़ने का अभियान चलाने का फैसला किया है। दुनिया की एक चौथाई सहकारी संस्थाएं भारत में हैं, जिन्हें सक्रिय करते हुए प्रभावी बनाया जाएगा। भारत की सहकारिता के मॉडल को दुनिया के देश अपनाने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने वैश्विक सम्मेलन के दौरान भारतीय सहकारी संस्थाओं में अपनी रुचि दिखाई है, जिसका लाभ भारतीय सहकारिता को होने वाला है। सहकारिता वर्ष में देश के सुदूर क्षेत्रों में सहकारिता की अलख जगाने का फैसला किया गया है। पूरे वर्ष के दौरान सहकारिता का प्रचार-प्रसार पूरी दुनिया में होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन देशों में सहकारिता के अच्छे कार्य हो रहे होंगे उन्हें दूसरे देशों में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। भारत की सहकारिता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। ■

4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

वैश्विक स्तर पर सहकार से समृद्धि की गूंज

भारतीय सहकारिता के क्रांतिकारी सुधारों को दुनिया ने सराहा

सहकार उदय टीम

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन और आईसीए की महासभा की बैठक में भारतीय सहकारिता की गूंज रही। दुनियाभर से आये सहकारी नेताओं और सौ से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की सहकारिता से लोगों के जीवन स्तर में आए क्रांतिकारी सुधार को जमकर सराहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करते हुए भारत में सहकारी क्षेत्र की महत्ता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा 'दुनिया के लिए सहकारिता एक मॉडल है, लेकिन भारत के लिए सहकारिता संस्कृति का आधार और जीवन शैली है।'

देश में बहुआयामी विकास को मजबूती देने और ग्रामीण भारत व किसानों की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाले '*सहकार से समृद्धि*' के दृष्टिकोण को सफल बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र में भी विकास, विस्तार और बदलाव के नवयुग का प्रारंभ हुआ है। भारतीय सहकारिता की इस सफलता से प्रेरित और प्रभावित होकर ही भारत में वैश्विक सहकारी आंदोलन के अग्रणी निकाय 'अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन' (आईसीए) के वैश्विक सहकारी सम्मेलन और महासभा का आयोजन किया गया। भारत में यह पहली बार हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने के फैसले का उद्देश्य दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने में सहकारी उद्यमों की शक्ति को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि '*सहकार से समृद्धि*' के दृष्टिकोण का लक्ष्य

- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ
- आईसीए सम्मेलन की थीम *सहकार से समृद्धि* से प्रेरित 'सहकारिता सबकी समृद्धि का द्वार'
- सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना ही सरकार की प्रतिबद्धता
- ग्रामीण भारत के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से को कवर करती हैं सहकारी समितियां

सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। प्रशासनिक और नीतिगत सुधारों एवं विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों से सहकारी क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। देश की सदियों पुरानी संस्कृति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा 'वेद-उपनिषद और अन्य

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 6/32

भारतीय धर्मग्रंथों में हम सभी को एक साथ चलने और एक स्वर में बोलने की बात कही गई है। ये ग्रंथ हमें शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व के साथ रहने को कहते हैं। यही सद्भाव सहकारिता की उत्पत्ति का मूल है और यह भारतीय परिवारों का भी अभिन्न अंग है।'

नई दिल्ली के भव्य भारत मंडपम में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे, फिजी के उप प्रधानमंत्री मनोआ कामिकामिका, भारत में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक श्री शोम्बी शार्प, अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के अध्यक्ष श्री एरियल ग्वार्को और 100 से अधिक देशों के करीब 3,000 से अधिक प्रतिनिधियों एवं सहकारी नेताओं का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभिनंदन देश के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, आठ लाख से अधिक सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 करोड़ महिलाओं एवं सहकारिता के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ने वाले युवाओं की ओर से है। भारत ने विश्वास जताया कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन से भारत की सहकारी यात्रा को आवश्यक अंतर्दृष्टि मिलेगी और वैश्विक सहकारिता को भी भारत के सहकारिता के समृद्ध अनुभव का लाभ मिलेगा।

विकसित भारत की ओर बढ़ रहे कदम

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में शासन को सहकारिता के साथ जोड़कर देश को विकसित देश बनाने की दिशा में काम हो रहा है। देश में आठ लाख सहकारी समितियां हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया की हर चौथी समिति भारत में है। सहकारी समितियां ग्रामीण भारत के लगभग 98 प्रतिशत हिस्से को कवर करती हैं और करीब 30 करोड़ देशवासी, यानी हर पांचवां भारतीय सहकारी क्षेत्र से जुड़ा है। भारत में शहरी और आवासीय सहकारी समितियों का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। देश में सहकारी समितियां चीनी, उर्वरक, मत्स्य पालन और दूध उत्पादन उद्योगों में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। भारत में लगभग दो लाख आवास सहकारी समितियां हैं। भारत के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के सहकारी बैंकों में अब 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा हैं, जो इन संस्थाओं के प्रति बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। सरकार ने सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूती देने के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जिसमें सहकारी बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में लाना और जमा बीमा कवरेज को बढ़ाकर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपए करना शामिल है। इन सुधारों से भारतीय सहकारी बैंकों को अधिक सुरक्षित व कुशल वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित करने में मदद मिली है।

सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

भारत में सहकारी क्षेत्र में महिलाओं की

4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

बड़ी भूमिका है। देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का दौर चल रहा है और इस सदी के वैश्विक विकास में महिलाओं की भागीदारी एक प्रमुख कारक बनने जा रही है। देश की महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक है और कई महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियां भारत के सहकारी क्षेत्र की ताकत बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कोई देश या समाज महिलाओं को जितनी अधिक भागीदारी देगा, वह उतनी ही तेजी से विकास करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सहकारी समितियों के प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। सरकार ने इस दिशा में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है और बहु-राज्य सहकारी समिति के बोर्ड में महिला निदेशकों का होना अनिवार्य कर दिया है। वंचित वर्गों की भागीदारी और समितियों को अधिक समावेशी बनाने के लिए उनमें आरक्षण भी दिया गया है।

स्वयं सहायता समूहों के रूप में महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के व्यापक आंदोलन का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दस वर्षों में इन स्वयं सहायता समूहों को नौ लाख करोड़ रुपए का सस्ता ऋण दिया है। इन स्वयं सहायता समूहों ने गांवों में बहुत अधिक संपत्ति अर्जित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे दुनिया के कई देशों में महिला सशक्तिकरण के 'मेगा मॉडल' के रूप में अपनाया जा सकता है।

> "संयुक्त राष्ट्र संघ सहकारी समितियों को सतत विकास का महत्वपूर्ण सूत्रधार मानती है। दुनिया में असमानता कम करने, बेहतर कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने और गरीबी उन्मूलन में इनकी प्रमुख भूमिका है। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में विश्व की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने में सहकारिता प्रयासों की वैश्विक पहल होगी।"
>
> - श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

छोटे किसानों को सहयोग देने को प्रतिबद्ध

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन के माध्यम से छोटे किसानों को सहयोग देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के छोटे किसानों को एफपीओ में संगठित कर रही है। इन संगठनों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जा रहा है। देश में लगभग 9,000 एफपीओ पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका उद्देश्य खेत से लेकर रसोई और बाजार तक कृषि सहकारी समितियों के लिए एक मजबूत आपूर्ति एवं मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना है। सरकार का प्रयास कृषि उत्पादों के लिए एक निर्बाध लिंक बनाना है जिसमें दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाया जा सके। सहकारी समितियों की पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 8/32

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता की बढ़ती भूमिका पर बोले प्रधानमंत्री

वैश्विक कोऑपरेटिव फाइनेंस संस्थान की जरूरत

सहकार उदय टीम

वैश्विक सहकारी क्षितिज पर आईसीए की बड़ी भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर में सहकारी समितियों को वित्तपोषित करने में सक्षम वैश्विक वित्तीय संस्थान के निर्माण की जरूरत है। इसके बल पर ही सहकारिता दुनिया में अखंडता एवं आपसी सम्मान का ध्वजवाहक बन सकती है। 21वीं सदी में हम वैश्विक सहकारिता आंदोलन की दिशा तय कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे सामूहिक वित्तीय मॉडल के बारे में सोचना होगा जो सहकारी वित्तीय प्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बना सकती है।

- सहकारी समितियों के लिए सरल एवं पारदर्शी वित्तपोषण सुनिश्चित करना समय की मांग है
- सहकारिता को दुनिया में अखंडता एवं आपसी सम्मान का ध्वजवाहक बनाने की जरूरत

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में वैश्विक सहकारी नेताओं से अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें छोटी कोऑपरेटिव्स के लिए सरल एवं पारदर्शी वित्तपोषण सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए कोऑपरेटिव वित्तीय मॉडल के बारे में सोचना होगा। छोटी व आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी समितियों को सहायता देने के लिए वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के साझा वित्तीय मंच बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण और सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने खरीद, उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेकर आपूर्ति शृंखला को बढ़ाने में सहकारी समितियों की क्षमता पर विश्वास जताया।

सहकारिता के महत्व पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह केवल संरचना, नियम व विनियमन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनसे संस्थाएं बनाई जा सकती हैं और इनका आगे और भी विकास एवं विस्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता की भावना सबसे महत्वपूर्ण है तथा सहकारिता की भावना ही इस आंदोलन की जीवन शक्ति है, जो सहकारिता की संस्कृति से आती है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सहकारिता की सफलता उनकी संख्या पर नहीं, बल्कि उनके सदस्यों के नैतिक विकास पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि जब नैतिकता होगी, तो मानवता के हित में सही निर्णय लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत का मानना है कि सहकारिता वैश्विक सहयोग को नई ऊर्जा दे सकती है। सहकारिता वैश्विक दक्षिणी देशों को उस तरह का विकास हासिल करने में मदद कर सकती हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। श्री मोदी ने इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु सहकारिता के नए तरीके खोजने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इस दिशा में आईसीए का यह वैश्विक सम्मेलन बहुत मददगार हो सकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता को दुनिया में अखंडता एवं आपसी सम्मान का ध्वजवाहक बनाने की जरूरत है। ■

लाने में डिजिटल प्लेटफार्मों की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार सहकारी समितियों को 'ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स' (ओएनडीसी) जैसे सार्वजनिक ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बना रही है। इससे सहकारी उत्पादों का सीधे उपभोक्ताओं तक सबसे सस्ती कीमतों पर पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा। सहकारी समितियों की बाजार उपस्थिति बढ़ाने का श्रेय सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) को देते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल कृषि को आधुनिक बनाने

और किसानों को सशक्त व प्रतिस्पर्धी बनाकर डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

सहकारिता में व्यापक सुधार

भारत अपने भविष्य के विकास में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका देखता है और इसलिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बड़े सुधारों के माध्यम से सहकारिता से जुड़े पूरे तंत्र में सुधार किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि सरकार का ध्येय सहकारी समितियों को बहुद्देशीय एवं मजबूत बनाना और उनके सदस्यों की आय बढ़ाना है। केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक अलग सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। सहकारी समितियों को बहुद्देशीय बनाने के लिए नए मॉडल उपनियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहकारी समितियों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ा है। डिजिटलीकरण के माध्यम से इन समितियों को जिला और राज्य स्तर पर सहकारी बैंकिंग संस्थानों से जोड़ा गया है। इन बुनियादी सुधारों से सहकारी समितियों को गांवों में कई तरह के कार्यों में शामिल करने में आसानी हुई है और इन्हें स्थानीय समाधान प्रदान करने वाले केंद्र चलाने, पेट्रोल और डीजल की खुदरा दुकानें चलाने, जल प्रबंधन का काम देखने और सौर पैनल लगाने जैसे काम मिल रहे हैं। कचरे से ऊर्जा के मंत्र के साथ सहकारी समितियां गोबरधन योजना में भी मदद कर रही हैं। सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में गांवों में डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही हैं। सरकार सहकारी समितियों की पहुंच

डाक टिकट जारी

सम्मेलन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जो सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की वचनबद्धता का प्रतीक है। टिकट पर कमल का पुष्प स्थिरता और सामुदायिक विकास के सहकारी मूल्यों को दर्शाता है। कमल की पांच पंखुड़ियां प्रकृति के पंचतत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। पर्यावरण, सामाजिक व आर्थिक स्थिरता के लिए सहकारी समितियों की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। इसमें कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियां और आवास जैसे क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं, जिसमें ड्रोन कृषि में आधुनिक तकनीक की भूमिका का प्रतीक है।

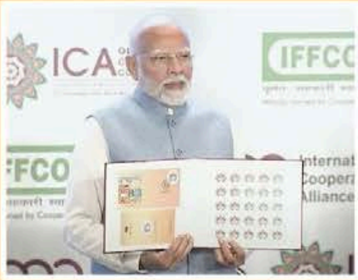

> संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दुनिया भर के करोड़ों गरीबों व किसानों के लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा।
>
> **- श्री अमित शाह**
>
> केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

से वंचित रहे गांवों में दो लाख बहुउद्देशीय सहकारी समितियां बना रही है और समितियों का विस्तार विनिर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र तक कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना पर काम कर रहा है। सहकारी समितियों द्वारा क्रियान्वित की जा रही इस योजना के तहत पूरे भारत में गोदाम बनाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को स्थानीय स्तर पर ही अपनी फसल सुरक्षित रखने में सुविधा होगी। इस पहल से छोटे किसानों को सबसे अधिक लाभ होगा।

सहकारिता से स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा भी सहकारिता से ही मिली थी। इससे न केवल आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों को एक सामाजिक मंच भी मिला। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज आंदोलन ने सामुदायिक भागीदारी को नई गति दी और खादी एवं ग्रामोद्योग की सहकारिताओं की मदद से एक नई क्रांति की शुरुआत की। श्री मोदी ने जोर देकर कहा 'सहकारिता ने ही खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रतिस्पर्धा में बड़े ब्रांडों से आगे निकलने में मदद की है।' सरदार पटेल ने दुग्ध सहकारी समितियों का उपयोग करके किसानों को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के युग में दूध उत्पादक किसानों के एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ अमूल सहकारिता के शीर्ष वैश्विक ब्रांडों में से एक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सहकारिता ने विचार से आंदोलन, आंदोलन से क्रांति और क्रांति से सशक्तिकरण तक का सफर तय किया है।■

समावेशी विकास से हो रहा गरीब कल्याण

समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इस विकास का लाभ सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने भारत और विश्व स्तर पर विकास को मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से देखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हमारे सभी कार्यों में मानव-केंद्रित भावनाएं प्रबल होनी चाहिए। कोविड-19 संकट के दौरान भारत की वैश्विक पहल का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि कैसे भारत दुनिया खासकर वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ आवश्यक दवाइयां और टीके साझा करके साथ खड़ा रहा।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025

किसानों और महिलाओं को सम्मान से जीने का रास्ता खोलेगा

सहकार उदय टीम

भारत में सहकारिता आंदोलन ने गांवों, किसानों, महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए कई रास्ते खोले हैं। सहकारिता के माध्यम से आने दिनों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए '*सहकार से समृद्धि*' के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (आईसीए) के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन-2024 के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने का फैसला दुनिया भर के लोगों के लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा। विश्व के करोड़ों गरीबों, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान से जीने का रास्ता खोलेगा। सहकारिता की पहुंच बढ़ाने के लिए भारत सरकार हर गांव और किसान को सहकारिता से जोड़ने के प्रति कटिबद्ध है और इस दिशा में सहकारिता मंत्रालय तेजी से नीतिगत पहल भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने तीन साल पहले सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और इन वर्षों में देश के हर व्यक्ति और क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाने के लिए बहुत काम हुआ है। सहकारिता के समग्र विकास के लिए आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। '*सहकार से समृद्धि*' के संकल्प से देश के लाखों गांवों, करोड़ों महिलाओं और किसानों की समृद्धि का रास्ता खुला और सहकारिता क्षेत्र में नई गतिविधियां शुरू हुईं।

- अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सहकारी नीति लाकर देश के सहकारी आंदोलन को नई दिशा देगी सरकार
- दुनिया के करोड़ों गरीबों व किसानों के लिए आशीर्वाद सिद्ध होगा वर्ष 2025 का अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
- आजादी के 75 वर्षों बाद देश के सहकारिता आंदोलन का हुआ पुनर्जन्म, आया एक नया जोश
- पैक्स को आधुनिक, तकनीकयुक्त और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने हेतु बड़े फैसले
- राष्ट्रीय स्तर पर बनी तीन नई सहकारी समितियों के माध्यम से भारत का किसान देश और दुनिया के बाजार तक पहुंचेगा
- सहकारिता विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षित और तकनीक से युक्त मानव संसाधन का होगा निर्माण

इससे भारत के सहकारिता आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ है और सहकारी क्षेत्र में एक नया जोश आया है। सरकार ने सहकारिता को मजबूती और विस्तार प्रदान करते हुए

4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

नए क्षेत्रों में कोऑपरिटिव की पहुंच बढ़ाने के विशेष प्रयास किए हैं। सहकारिता क्षेत्र के कानूनी ढांचे का सुदृढ़ीकरण हुआ है। श्वेत क्रांति 2.0 और नीली क्रांति की शुरुआत भी हुई है जिसमें सहकारिता का बहुत अहम भूमिका है। श्री शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में सहकारिता विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षित और तकनीक से युक्त मानव संसाधन का निर्माण होगा। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में सरकार नई सहकारी नीति लाकर भारत के सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने का काम करेगी।

इफको, कृभको और अमूल सहकारी क्षेत्र में दुनिया में नजीर बने

श्री अमित शाह ने कहा कि इफको, कृभको और अमूल ने सहकारिता के क्षेत्र में पूरी दुनिया में उदाहरण पेश किया है। ये तीनों कोऑपरेटिव्स दुनिया के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करेंगी। भारत सरकार देश में सहकारिता की पहुंच से अब तक वंचित रहे गांवों में सहकारी समितियों का प्रसार कर रही है। तीन सालों में दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स), डेयरी व मत्स्य समितियों की स्थापना के बाद भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा, जहां कोई सहकारी संस्था न हो।

श्री शाह ने कहा कि पैक्स को आधुनिक, तकनीकयुक्त बनाने और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए भी कई फैसले किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई तीन नई सहकारी कोऑपरेटिव्स- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) के माध्यम से आने वाले दिनों में भारतीय किसानों की पहुंच देश और दुनिया के बाजारों तक बढ़ेगी। यह दुनिया की सहकारी संस्थाओं के लिए प्रेरणादायक होगा कि किस प्रकार भारत के छोटे किसानों की भी पहुंच पूरी दुनिया के बाजारों तक बढ़ रही है।

तथ्य यह है कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद इस क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। देश में सहकारिता क्षेत्र का डेटाबेस तैयार कराया गया, जिससे नीतिगत फैसला करने में मदद मिली है।

नतीजतन, देश में सहकारिता को नई ऊर्जा प्राप्त हुई, जिससे निचली इकाई पैक्स से लेकर अपेक्स (शीर्ष) संस्था तक सशक्त हुई है। इसी क्रम में मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए मॉडल बायलॉज तैयार कराया, जिसे सभी प्रदेशों में लागू कर दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने सहकारिता से जुड़े सभी केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित कर उनकी योजनाओं का लाभ पैक्स तक पहुंचाने का फैसला लिया। इससे पैक्स का कारोबारी दायरा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार के अवसर सृजित हुए वहीं लोगों की आमदनी बढ़ाने में वृद्धि हुई है। गरीबों और भूमिहीन किसानों की आय में वृद्धि के लिए देश में कृषि, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में दो लाख से अधिक पैक्स के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पुराने निष्क्रिय पैक्स को जहां पुनर्संचालित किया जा रहा है वहीं नए पैक्स के गठन पर जोर दिया गया है।■

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 13/32

एनसीडीसी की 91वीं आम परिषद की बैठक

सहकारी समितियों को एकीकृत करने में राष्ट्रीय डेटाबेस की अहम भूमिका

सहकार उदय टीम

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार के इस काम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की अहम भूमिका है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को हाल ही में एनसीडीसी की 91वीं आम परिषद में साझा किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में एनसीडीसी के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि एनसीडीसी लाखों सहकारी समितियों के विकास, विस्तार और प्रगति में यह अहम भूमिका निभा रही है।

➲ सहकारी क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है सरकार : श्री अमित शाह

➲ सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में एनसीडीसी की भूमिका अहम है

एनसीडीसी ने 60,000 करोड़ रुपए का योगदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनसीडीसी के साथ सहकारी इंटर्न योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य और जिला सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बैठाने और पैक्स को मजबूत बनाने में मदद करना है। सहकारी इंटर्न योजना प्रतिभागियों को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करेगी और उन्हें सहकारिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों के विकास का समर्थन करने के लिए तैयार करेगी। श्री शाह ने देश भर में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प दोहराया। सहकारिता के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे *सहकार से समृद्धि* के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

श्री शाह ने सहकारी समितियों को एकीकृत करने में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीडीसी और सहकारिता मंत्रालय इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना वर्तमान समय की मांग है। दूध उत्पादक संघों की स्थापना के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और एनसीडीसी के बीच सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह पहल न केवल श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाएगी, बल्कि आदिवासी समुदायों और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

सरकार ने डिजिटल क्रांति के माध्यम से बनाया न्याय प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी

सहकार उदय टीम

➲ आगामी 10 वर्षों में दुनिया में सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक और त्वरित होगी भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के समग्र विकास और देशवासियों के हितों की रक्षा की दिशा में बहुआयामी कदम बढ़ा रही है। भारत की आंतरिक सुरक्षा और आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत क्रांतिकारी और आमूलचूल बदलाव हुआ है। प्रत्येक नागरिक को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इन विचारों को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन के स्वर्ण जयंती समारोह में व्यक्त किया और कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा और संविधान प्रदत्त अधिकारों को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में भारत का आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक, वैज्ञानिक और तेज होगा। इन कानूनों पर पूरी तरह अमल होने के बाद किसी भी मामले में देशवासियों को तीन साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिल जाएगा।

श्री शाह ने कहा कि पिछले कई दशकों में देश, दुनिया, अपराध जगत और पुलिसिंग में बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन इनके अनुरूप समयानुकूल अपेक्षित बदलावों में भारत पीछे रह गया था। ऐसे में, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समसामयिक चुनौतियों को समझते हुए नए आपराधिक कानूनों पर अमल की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके तहत सबसे पहले पुलिस व्यवस्था की अहम कड़ी के रूप में पुलिस स्टेशनों का कंप्युटरीकरण पूरा किया गया। देश के सभी 17,000 पुलिस स्टेशनों को डिजिटल माध्यम से 'क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स' (सीसीटीएनएस) के साथ और 22,000 अदालतों को ई-कोर्ट के साथ जोड़ दिया गया है। तीन नए आपराधिक कानूनों को लाने से पहले ही सरकार ने कोर्ट, अभियोजन, पुलिस, जेल और फोरेंसिक साइंस प्रयोगशालाओं को जोड़ने की पूरी व्यवस्था बना ली थी।

नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति को किया मजबूत

श्री शाह ने कहा कि दशकों से कश्मीर, पूर्वोत्तर और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र अशांत माने जाते थे, लेकिन सरकार ने सुरक्षा स्थिति को सशक्त कर इन क्षेत्रों की स्थिति में बहुत सुधार किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में सरकार इससे पहले के 10 वर्षों की तुलना में हिंसा में लगभग 70 प्रतिशत कमी लाने में सफल रही है। इन वर्षों में सरकार ने 35,000 करोड़ रूपए मूल्य के 5,45000 किलोग्राम नार्कोटिक्स को जब्त किया है, जो इससे पहले के 10 वर्षों से छह गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में सरकार ने जब्ती की प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके से बदलने में सफलता हासिल की है।

श्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत सहित पूरी दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं जिनके हल ढूंढने के प्रयास करने होंगे। ■

मन की बात की 116वीं कड़ी में बोले प्रधानमंत्री श्री मोदी...

विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका

सहकार उदय टीम

देश के सामूहिक प्रयासों, भारत की उपलब्धियों, जन-जन के सामर्थ्य और देश की युवा शक्ति के सपनों एवं देशवासियों की आकांक्षाओं की बात ही मेरे 'मन की बात' है। इन विचारों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में साझा किया। देश की युवा शक्ति पर विशेष फोकस करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन और चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। उन्होंने आगामी वर्ष तक राजनीति में एक लाख नए युवाओं को लाने पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है, जिनके पूरे परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इस दिशा में पहल करते हुए सरकार नए साल में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' का आयोजन कर रही है। यह प्रयास ऐसे नए और युवा नेताओं को सामने लाने के लिए है, जो देश की राजनीति में परिवर्तन लाने में सक्षम हों।

यह भव्य कार्यक्रम देश भर के करोड़ों युवाओं को एकजुट होने, विचार-विमर्श करने और भारत के भविष्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने का मंच प्रदान करेगा। इस अखिल भारतीय आयोजन में देश के सभी राज्यों, जिलों, प्रखंडों व गांवों से प्रतियोगी चरणों से चुने गए करीब 2000 युवा शक्ति की भागीदारी होगी। इसमें देश और विदेश से विशेषज्ञ आएंगे और अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी रहेंगी, जहां भारतीय युवाओं को सीधे हमारे सामने अपने विचारों को रखने का अवसर मिलेगा।

- अगले साल तक एक लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का लक्ष्य
- दुनिया भर में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में भारत बसता है

श्री मोदी ने विश्वास जताया कि देश की युवा शक्ति की सक्षम भागीदारी से ही भारत के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होगा। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं।

निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे युवा

श्री मोदी ने कहा कि वे 'मन की बात' में अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं,

4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही युवा हैं जो लोगों की छोटी-छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। कुछ युवाओं ने समूह बनाकर भी इस तरह के सार्थक प्रयासों को सफल किया है।

उन्होंने लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र का उदाहरण दिया, जो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद कर रहे हैं। बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत न आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है, जो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि कई शहरों में 'युवा' बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं।

भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। बुजुर्गों को 'डिजिटल अरेस्ट' के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव क्षेत्रीय लोगों को इस खतरे से आगाह करते हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में यह सामुहिक दायित्व है कि समाज उन्हें जागरूक बनाए और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करे। इसके लिए लोगों को बार-बार समझाना होगा कि 'डिजिटल अरेस्ट' नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है और यह सब सरासर झूठ, लोगों को फसाने का एक षड्यन्त्र है। प्रधानमंत्री ने इस काम में युवाओं के पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा लेने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन रहा है।

कर्नाटक के मैसूर की एक संस्था ने बच्चों के लिए 'अर्ली बर्ड' नाम का अभियान शुरू कर बच्चों को पक्षियों के बारे में बताने के लिए खास तरह की लाइब्रेरी चला रही है। संस्था ने बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए 'नेचर एजुकेशन किट' तैयार किया है। ये संस्था शहर के बच्चों को गांवों में लेकर जाती है और उन्हें पक्षियों के बारे में बताती है और इन प्रयासों की वजह से बच्चे पक्षियों की अनेक प्रजातियों को पहचानने लगे हैं। कार्पोरेट दुनिया की चमक-दमक छोड़कर इतिशा अरुणाचल की सांगती घाटी को साफ बनाने में जुटी हैं।

'एक पेड़ मां के नाम' व स्वच्छता अभियान ने किया कमाल

श्री मोदी ने कुछ महीने पहले देश में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान शुरू होने और इसमें देशवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस अभियान ने सिर्फ पांच महीनों में सौ करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह जानकर सभी को गर्व होगा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। अभी हाल ही में गुयाना में वहां के राष्ट्रपति डॉ. इरफान अली सपरिवार मेरे साथ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में यह अभियान लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत रिकॉर्ड पेड़ लगाए गए और 24 घंटे में ही 12 लाख से ज्यादा पौधरोपण हुआ। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब हरित जोन में बदल जाएंगे। साफ-सफाई को लेकर यूपी के कानपुर नगर में भी अच्छी पहल हो रही है, जहां कुछ लोग रोज सुबह की सैर पर जब गंगा किनारे निकलते हैं तो वे गंगा के घाटों पर फैले प्लास्टिक और अन्य कचरे को उठा लेते हैं। धीरे-धीरे यह जन भागीदारी का बड़ा अभियान बन गया है और शहर के कई लोग 'कानपुर प्लागर्स ग्रुप' के साथ जुड़कर अब नगर की दुकानों और घरों से भी कचरा उठाने लगे हैं। इस कचरे को रिसाइकल करके पेड़ों की सुरक्षा कवच तैयार हो रहे हैं, जिनसे पौधों की सुरक्षा भी हो रही है। ऐसे प्रयासों से भारत के स्वच्छता अभियान को गति मिली है।

युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण में एनसीसी का अहम रोल

इस विशेष अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) दिवस होने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने स्वयं की एनसीसी कैडेट के रूप में भागीदारी को याद किया और लाखों युवाओं के जीवन को दिशा देने वाले एनसीसी के महत्व पर कहा, 'एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। जब भी कहीं कोई आपदा आती है, चाहे वह बाढ़, भूकंप या कोई दुर्घटना हो, एनसीसी के कैडेट मदद के लिए वहां जरूर मौजूद होते हैं।' उन्होंने कहा कि आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। वर्ष 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे, जबकि 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के मुकाबले पांच हजार नए स्कूल-कॉलेजों में एनसीसी की सुविधा बढ़ा दी गई है।

उन्होंने एनसीसी में पहले 25 प्रतिशत के मुकाबले गर्ल्स कैडेट की संख्या बढ़कर अब करीब 40 प्रतिशत पहुंचने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले युवाओं को एनसीसी से ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। श्री मोदी ने युवाओं का आह्वान किया कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़ें। इससे युवाओं को उनके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी।■

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 17/32

4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा भारत : प्रधानमंत्री

- भौतिक, सामाजिक व डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति पथ पर भारत
- भारत मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अग्रणी देश बन गया है : प्रधानमंत्री
- जर्मनी का 'फोकस ऑन इंडिया' दस्तावेज दर्शाता है कि दुनिया भारत के रणनीतिक महत्व को पहचान रही है

सहकार उदय टीम

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके साथ विकास के लिए साझेदारी करने में दुनिया की रुचि है। जर्मनी का 'फोकस ऑन इंडिया' दस्तावेज यह दर्शाता है कि दुनिया भारत के रणनीतिक महत्व को पहचान रही है। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। यह बदलाव पिछले दस वर्षों में भारत में हुए सुधारों के कारण हुआ है, जिससे व्यापार की स्थितियों में सुधार किया है, नौकरशाही का दखल कम किया है और सभी क्षेत्रों में नीतियों का आधुनिकीकरण हुआ है। इन तथ्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित एक वैश्विक समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से व्यक्त किया।

सरकार ने जीएसटी के साथ कर प्रणाली को सरल बनाया है। 30,000 से अधिक प्रावधानों को समाप्त किया गया है और बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। इन प्रयासों ने भारत के भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जिसमें जर्मनी इस यात्रा में एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि जर्मनी जिस प्रकार विनिर्माण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत भी उसके समानांतर वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत निर्माताओं को उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन दे रहा है। भारत महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में अग्रणी देश बन गया है। हम दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया वाहन उत्पादक और स्टील व सीमेंट के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक बन गए हैं। यह परिवर्तन वैश्विक विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। भारत चार पहिया वाहनों का चौथा सबसे बड़ा निर्माता भी है और इसका सेमीकंडक्टर उद्योग वैश्विक सफलता के लिए तैयार है। इस प्रगति का श्रेय हाल ही में सरकार की नीतियों को जाता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे में सुधार, रसद लागत को कम करना, व्यापार संचालन को आसान बनाना और स्थिर शासन सुनिश्चित करना है। भारत भौतिक, सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में तेजी से प्रगति कर रहा है, जिसका अपनी अभिनव डिजिटल प्रौद्योगिकियों से उल्लेखनीय वैश्विक प्रभाव है।

25 वर्षों पुरानी है भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी 25 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। जर्मनी भू-राजनीतिक संबंधों, व्यापार और निवेश के मामले में भारत के प्रमुख साझेदारों में से एक है। एक जर्मन व्यक्ति ने ही यूरोप की पहली संस्कृत व्याकरण पुस्तकें लिखीं हैं और जर्मन व्यापारियों ने तमिल और तेलुगु मुद्रण को यूरोप में पेश किया है। श्री मोदी ने कहा, 'आज जर्मनी में लगभग 300,000 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 50,000 भारतीय छात्र वहां पढ़ते हैं। पिछले तीन-चार वर्षों में 1,800 से अधिक जर्मन कंपनियों ने भारत में 15 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।' दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 34 बिलियन डॉलर का है, जो मजबूत होती साझेदारी से आने वाले वर्षों में आगे की ओर बढ़ता रहेगा। उन्होंने भारत में पहले से स्थापित जर्मन कंपनियों को अपना निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और जो अभी तक मौजूद नहीं हैं, उन्हें भारतीय बाजार में प्रवेश करने का आह्वान किया। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत के विकास के साथ तालमेल बिठाने का यह सही समय है, प्रधानमंत्री ने भारत की गतिशीलता और जर्मनी की सटीकता, इंजीनियरिंग और नवाचार के बीच साझेदारी का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि एक प्राचीन सभ्यता के रूप में भारत ने हमेशा वैश्विक साझेदारी का स्वागत किया है और सभी को दुनिया के लिए एक समृद्ध भविष्य के निर्माण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 18/32

ब्राजील में जी 20 सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री

भूख और गरीबी से निपटने की भारत की पहल

सहकार उदय टीम

भारत ने पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। 55 करोड़ भारतीय दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और अब 70 वर्ष से अधिक आयु के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। भूख और गरीबी से निपटने की भारत की पहल को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के रियो-डि-जेनेरियो में जी 20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वैश्विक मंच पर साझा किया। 'सामाजिक समावेश तथा भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई' विषय पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने खाद्य सुरक्षा से निपटने में भारत की सफलता पर जोर देकर कहा कि 'मूलभूत बातों पर वापस आने और भविष्य की ओर आगे बढ़ने' के दृष्टिकोण से यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया और कहा कि भारत की जी-20 अध्यक्षता का 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का आह्वान रियो में भी गूंज रहा है। प्रधानमंत्री ने भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन स्थापित करने की ब्राजील की पहल का स्वागत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक दक्षिण के देशों की चिंताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को नि:शुल्क खाद्यान्न दे रही सरकार
- 55 करोड़ भारतीयों को सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

जन-केंद्रित योजनाओं से संवर रहा भारतीय जन-जीवन

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन-केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाया गया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दिए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और वैश्विक दक्षिण के देशों की आशाओं और आकांक्षाओं को पंख दिए। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और सामाजिक समावेश की दिशा में सार्थक पहल करते हुए भारत ने सूक्ष्म क्षेत्र की 30 करोड़ से अधिक महिला उद्यमियों को बैंकों से जोड़ा गया है और उन्हें ऋण सुविधा दी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना के तहत चार करोड़ से अधिक किसानों को 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ मिला है। किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 40 बिलियन डॉलर से अधिक की सहायता दी गई है। किसानों को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि पोषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अभियान के तहत महिलाओं, नवजात शिशुओं, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरियों के पोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सरकार 'मिड डे मील' योजना के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने वैश्विक मंच से कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। भारत ने हाल ही में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को मानवीय सहायता प्रदान की है।

जैविक खेती के साथ ही नई तकनीकों पर भी भारत का ध्यान

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने न केवल प्राकृतिक खेती और जैविक खेती पर, बल्कि नई तकनीकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हमारा देश श्री अन्न या मोटे अनाजों को बढ़ावा देकर सतत कृषि, पर्यावरण की सुरक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। भारत ने 2000 से अधिक जलवायु प्रतिरोधी फसल किस्में विकसित की हैं और 'डिजिटल कृषि मिशन' की शुरुआत की है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे ने सामाजिक और वित्तीय समावेश को सक्षम बनाया है। आकांक्षी जिलों और प्रखंडों की परियोजना के साथ भारत ने समावेशी विकास के लिए एक नया मॉडल बनाया है, जो समाज के सबसे गरीब व कमजोर लोगों को मजबूती देने पर आधारित है। ■

धर्मांतरण विरोधी आंदोलन के लिए भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा देश

सहकार उदय टीम

➲ रांची की जेल से इंग्लैंड तक देशवासियों की आवाज बने राष्ट्र नायक बिरसा मुंडा

➲ जल, जंगल और जमीन ही आदिवासियों के लिए सब कुछ है, इस संस्कार को बिरसा मुंडा ने पुनर्जीवित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बीते 10 वर्षों में जनजातीय गौरव के लिए ढेर सारे काम किए हैं और आदिवासी क्षेत्रों में विकास को रोकने वाले व नौजवानों को गुमराह करने वाले नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर नई दिल्ली के बांसेरा उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के मौके पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा

4/1/25, 4:23 PM Sahkar Uday 21st issue - Hindi

मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी। श्री बिरसा मुंडा ने ही आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन ही सब कुछ है, इस संस्कार को पुनर्जीवित किया। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आगामी एक वर्ष यानि कि 15 नवंबर 2025 तक 'आदिवासी गौरव वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।

सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती वर्ष के अवसर पर सराय काले खां चौक का नाम बदलकर 'भगवान बिरसा मुंडा चौक' कर दिया है। श्री शाह ने कहा कि पहले की सरकार में जनजातियों के विकास के लिए बजट सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए का था, जिसे श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बढ़ाते हुए वर्ष 2024-25 के बजट में 1,33,000 करोड़ रुपए किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 26,428 आदिवासी गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन योजना के तहत 97,000 हजार करोड़ रुपए एकत्रित हुए। इसके साथ ही 708 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल बनाए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए 'पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन' के तहत 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों का विकास हो रहा है।

भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के संस्कार को किया पुनर्जीवित

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल और जमीन के संस्कार को पुनर्जीवित किया और कहा कि आदिवासियों के लिए यही सब कुछ है। बिरसा मुंडा ने समाज में कई प्रकार की जागरूकता लाने का अभियान चलाया और मदिरा पान, जमींदारों की शोषण युक्त व्यवस्था और ब्रिटिश राज का विरोध किया।

भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक तो बने ही, साथ ही उन्होंने 25 वर्ष की अल्पायु में अपने कर्मों के माध्यम से देशवासियों को जीवन का ध्येय समझाया कि जीवन कैसा व किसके लिए होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक हैं। जब पूरे भारत एवं दो-तिहाई दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी सेकंडरी शिक्षा के दौरान अल्पायु में ही धर्मांतरण के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होने की वीरता दिखाई। आगे चलकर उनकी इस दृढ़ता व वीरता ने उन्हें देश के एक ऐसे राष्ट्र नायक के रूप में बदल दिया, जिसकी आवाज रांची की जेल से इंग्लैंड की महारानी तक गूंजती थी। श्री शाह ने कहा कि सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता संघर्ष एवं धर्मांतरण विरोधी आंदोलन के लिए पूरा देश सदैव भगवान बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा।

'धरती आबा' ने आदिवासी संस्कृति की रक्षा और आजादी की अलख जगाई

श्री शाह ने कहा कि 'धरती आबा' के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को दो हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला आदिवासी संस्कृति की रक्षा को लेकर उनकी प्रतिबद्धता है जबकि दूसरा मातृभूमि की आजादी और इसकी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा। अपने जीवन के उद्देश्यों और कार्यों के माध्यम से बिरसा मुंडा ने देशवासियों के लिए इस बात का एक बेहतरीन नजीर पेश किया कि जीवन कैसा व किसके लिए होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से सभी को देश के लिए जीने और मरने का ध्येय प्रस्तुत किया। निश्चित तौर पर भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक हैं। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की ज्योति जगाई और आदिवासियों की स्थिति की तरफ न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचकर अपने कार्यों से ऐसी गाथा लिखी कि 150 वर्षों बाद भी पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आचरण से ऐसी गौरव गाथा लिखी है कि देश की जनता सदैव उनके सामने नतमस्तक रहेगी और भारतीय जवानों की पीढ़ियां देश की अस्मिता की रक्षा की प्रेरणा लेती रहेंगी। आदिवासियों के लिए अपनी मूल संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने का उनका वीरतापूर्ण कार्य सदैव ही भारतीय जनमानस को प्रेरणा देता रहेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि आदिवासियों ने देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर भाग लिया, लेकिन आजादी के बाद इन महानायकों को भुला दिया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 200 करोड़ रुपए की लागत से देशभर में आदिवासी महानायकों के संग्रहालय बनाने और विरासत को संचित करने का निर्णय लिया। अब तक तीन संग्रहालय बन गए हैं और प्रधानमंत्री श्री मोदी रांची में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय, जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय एवं छिंदवाड़ा में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी कर चुके हैं। वर्ष 2026 तक शेष सभी संग्रहालयों के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा।

https://online.pubhtml5.com/dhhsc/jcqg/ 21/32

गांवों की तरक्की में जिला सहकारी बैंकों की अहम भूमिका- श्री अमित शाह

सहकार उदय टीम

भारत जैसे विशाल देश में लगभग 13 करोड़ किसानों को बिना किसी तकलीफ के लघु अवधि का कृषि ऋण मिलने की व्यवस्था ने पूरे देश के किसानों और कृषि क्षेत्र में नई जान डालने का काम नैफकब ने किया है। किसी भी संस्था की हीरक जयंती के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं पहला, संस्था द्वारा 60 साल के अपने योगदान और उपलब्धियों को जनता के सामने रखना, दूसरा, अपनी गलतियों को देखकर उनमें सुधार करना। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), जिला और राज्य सहकारी बैंक के त्रिस्तरीय ढांचे के बिना भारत की खेती, किसानों और गांवों द्वारा आजादी के 75 साल की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करना असंभव था।

- देश के 13 करोड़ किसानों को बिना बाधा के लघु अवधि का कृषि ऋण उपलब्ध कराता है नैफकब
- नैफकब के हीरक जयंती समारोह और ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक में पहुंचे श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड (नैफकब) के हीरक जयंती समारोह में उपरोक्त बातें कहीं। नैफकब की हीरक जयंती और ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने पहुंचे श्री अमित शाह ने कहा कि जिला और राज्य स्तरीय बैंकों ने न सिर्फ लघु अवधि के कृषि ऋण की चिंता की, बल्कि सामूहिक खेती, जल प्रबंधन, खेती में काम आने वाली सामग्री और व्यक्तिगत काम से लेकर गांवों को मजबूत करने का लगभग हर काम जिलास्तरीय बैंक और पैक्स ने किया। राज्य सहकारी बैंकों ने ग्रामीण स्तर के इन बैंकों को आधार दिया। श्री शाह ने कहा कि जिला सहकारी बैंकों से जुड़े सभी कोऑपरेटिव के बैंक अकाउंट अगर जिला सहकारी बैंक में आ जाते हैं तो अपने आप 20 प्रतिशत लो कॉस्ट डिपॉजिट में वृद्धि हो जाएगी, और जब लो कॉस्ट या न्यूनतम जमापूंजी बढ़ती है तो मुनाफा भी अपने आप बढ़ जाता है, जिससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता भी बढ़ेगी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, सहकार से समृद्धि के मंत्र में ही सहकारिता मंत्रालय की स्थापना का उद्देश्य भी समाहित है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत में अमूल के माध्यम से बहुत ही सही तरीके से श्वेत क्रांति हुई है, अमूल का टर्नओवर अब 80,000 करोड़ रुपए का है, यह सारा टर्नओवर अब जिला सहकारी बैंकों के माध्यम से होता है। इस मॉडल को हर जिला सहकारी बैंक को अपनाना चाहिए और अपनी ताकत और आत्मविश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए। राज्य सहकारी बैंकों का मुनाफा लगभग 2400 करोड़ रुपए है और जिला सहकारी बैंकों का मुनाफा 1881 करोड़ रुपए है, हमें इसमें वृद्धि का लक्ष्य तय करना चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री मुरलीधर मोहोल और सचिव, सहकारिता सहित कई लोग उपस्थित थे।

देशभर के कृषि ऋण का लेखा जोखा नैफकब के पास

वर्ष 1964 में डॉ गाडगिल और मगनभाई पटेल ने दूरदर्शिता के साथ नैफकब की स्थापना की गई। अलग-अलग प्रयासों के माध्यम से नैफकब ने देश के जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय बैंकों का मार्गदर्शन और मदद करने का काम किया है। नैफकब एकमात्र ऐसा संस्थान है जो राज्य स्तरीय, जिलास्तरीय बैंकों और हजारों पैक्स के 100 बुनियादी मापदंडों का अधिकृत डेटा अपना पास रखता है जिसके आधार पर देशभर के कृषि ऋण का खाका खींचा जाता है। इस डेटा की पारदर्शी और सटीक 99.72 प्रतिशत पाई गई है। सहकारी ऋण, बैंकिंग और इनसे संबंधित समस्याओं की जांच करने और समाधान के लिए और रणनीति बनाने के लिए नैफकब की स्थापना की गई थी।

पैक्स और जिला सहकारी बैंकों ने जीते उत्कृष्टता पुरस्कार

नैफकब का देशभर में नेटवर्क

- नैफकब में 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, 352 जिला स्तरीय सहकारी बैंक हैं।
- इसके साथ ही 105000 पैक्स हैं, जिनमें फिलहाल लगभग 65000 कार्यरत हैं।
- जिला सहकारी बैंकों में कुल 433000 करोड़ रुपए जमा हैं और राज्य सहकारी बैंकों में 2,42,000 करोड़ रुपए जमा हैं।
- अगले पांच साल में देश में 80 जिलों में जिला सहकारी बैंक खोलना सरकार लक्ष्य है।

सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सम्मानित किया। भारत मंडपम में आयोजित नैफकब का हीरक जयंती समारोह इन उपलब्धियों का साक्षी बना। श्री शाह ने कहा कि जब तक पैक्स तकनीक से लैस नहीं होते थे इसकी कार्यप्रणाली में प्रशासनिक पारदर्शिता का अभाव था। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सरकार ने पैक्स की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल दिया। पैक्स की परंपरागत कार्यप्रणाली में बदलाव होने से वह अधिक वायबल या व्यावहारिक हो गए हैं। श्री शाह ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि नये युवाओं को न केवल सहकारिता से जोड़ा जाए बल्कि पैक्स के कामकाज में भी युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राज्य सहकारी बैंकों के शीर्ष निकाय नैफकब के 60 साल पूरे होने के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें देशभर के ग्रामीण सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता के भाव को मजबूत करने के लिए गांव की हर समस्या का समाधान पैक्स के माध्यम से किया जाएगा। जिले की हर समस्या का समाधान कोऑपरेटिव या सहकारिता में होना चाहिए और राज्य की हर समस्या राज्य कोऑपरेटिव बैंकों की समस्या होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सबकी सहभागिता, सबका कल्याण और मुनाफे का समान वितरण ये तीनों संस्कार हमारे पैक्स या जिला कोऑपरेटिव बैंक को अपनाने होंगे। जिला कोऑपरेठिव बैंक और राज्य कोऑपरेठिव बैंकों के संचालन में पहले से अधिक पारदर्शिता है। नैफकब में इस समय 34 राज्य कोऑपरेटिव बैंक 352 जिला सहकारी बैंक और 105000 पैक्स हैं, जिसमें फिलहाल 65000 पैक्स कार्यरत है, इस पूरे तंत्र को एक साथ होकर काम करना होगा।

राज्य सहकारी बैंकों में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को सम्मानित किया गया जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर ने किया। जबकि केरल राज्य सहकारी बैंक का प्रतिनिधित्व इसके सीईओ जोर्टी एम. चाको ने किया। तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक का प्रतिनिधित्व इसके एमडी पी. लोगनाथन ने किया। गोवा राज्य सहकारी बैंक का पुरस्कार उसके अध्यक्ष उल्हास बी. फाल देसाई और सीईओ अनंत एम. चोडांकर को मिला। आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का पुरस्कार प्रबंध निदेशक श्रीनाथ रेड्डी ने प्राप्त किया। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष देवेंद्र श्याम और सीईओ शरवन मंटा और गुजरात राज्य सहकारी बैंक का प्रतिनिधित्व अजयभाई पटेल ने किया। मिजोरम सहकारी शीर्ष बैंक सिक्किम राज्य सहकारी बैंक और कर्नाटक राज्य सहकारी शीर्ष बैंक को भी पुरस्कृत किया गया। डीसीसीबी श्रेणी में कृष्णा डीसीसीबी की प्रभारी व्यक्ति गीतांजलि शर्मा और सीईओ श्याम मनोहर ने बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। इसी तरह सतारा डीसीसीबी की ओर से अध्यक्ष नितिन पाटिल और सीईओ राजेंद्र सरकाले ने शाह से पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य पुरस्कृत डीसीसीबी में सूरत डीसीसीबी, करीमनगर डीसीसीबी और अकोला डीसीसीबी शामिल थे।

सहकारी डेयरी आंदोलन से महिलाएं बनीं सशक्त और गांव हुए समृद्ध

सहकार उदय टीम

दुनिया के सभी देशों में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन की सबसे ज्यादा औसत भारत की है और इसमें सहकारी आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। जब सहकारिता क्षेत्र में डेयरी की शुरुआत की गई, उस समय किसी को नहीं पता था कि अमूल 60 हजार करोड़ रुपए का बड़ा तंत्र बन जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में 800 टन उत्पादन क्षमता वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सहकारी डेयरी आंदोलन ने न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, बल्कि गांवों में समृद्धि लाने और पोषण प्रदान करने में भी योगदान किया है। साबर डेयरी की स्थापना के रूप में जो बीज बोया गया था, वह अब एक वटवृक्ष के रूप में साढ़े तीन लाख से ज्यादा परिवारों की आजीविका का साधन बन चुका है। पशुपालन से जुड़ी महिलाएं साबर डेयरी और उसके दूध के व्यापार की वजह से सम्मान का जीवन जी रही हैं। श्री शाह ने कहा कि अमूल द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति के कारण यह सफलता देखने को मिली है।

- देश के किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का वैश्विक बाजार खोलने और उनकी समृद्धि का साधन बनेगी प्राकृतिक खेती
- साबर डेयरी के रूप में बोया गया बीज एक वटवृक्ष बनकर साढ़े तीन लाख से ज्यादा परिवारों की आजीविका का साधन बन चुका है
- राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) से किसानों को मिलेगा लाभकारी मूल्य

साबरकांठा के किसानों की चारा संबंधी जरूरतें होंगी पूरी

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि करीब 210 करोड़ रुपए की लागत से साबर डेयरी के पशु आहार संयंत्र स्थापना की गई है ताकि स्थानीय लोगों के मवेशियों को पोषक आहार मिल सके। यह अत्याधुनिक संयंत्र न केवल साबरकांठा और अरावली के किसानों की चारा संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। श्री शाह ने कहा कि वर्ष 1976 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक साबर डेयरी ने 2050 टन पशु आहार क्षमता हासिल की है। भारत में वर्ष 1970 में प्रतिदिन सिर्फ 40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दूध उपलब्ध था, जो कि उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 2023 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 167 किलोग्राम उपलब्धता रही है।

किसानों की समृद्धि का आधार बनेगी प्राकृतिक खेती

किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि प्राकृतिक खेती आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि का आधार बनेगी। यह देश एवं दुनिया के नागरिकों को कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्त करने का साधन भी बनेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती काफी आसान है और इससे समाज का स्वास्थ्य एवं आय बढ़ाने में काफी मदद मिल सकती है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनके उत्पाद के लिए अच्छी कीमत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है, जो किसानों से प्राकृतिक खेती से उगाये गए उत्पाद खरीद कर उनका निर्यात करेगी। ■

श्वेत क्रांति के जनक- डॉ वर्गीज कुरियन

सहकार उदय टीम

डॉ वर्गीज कुरियन को भारत की श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। वर्ष 1965 से 1998 तक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष रहे डॉक्टर कुरियन की बदौलत वर्ष 1970 के दशक में भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध की उपलब्धता संभव हो पाई। देश में जब दूध का उत्पादन काफी कम था और जनसंख्या अधिक थी उस समय सभी को दूध उपलब्ध नहीं था, लेकिन डॉ वर्गीज कुरियन की दूरदर्शिता के कारण देश में श्वेत क्रांति संभव हो पाई और देश दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया। डेयरी क्षेत्र में डॉ वर्गीज के योगदान के कारण वर्ष 2001 में आईसीए ने उन्हें रोशडेल पायनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया।

मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉ कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में केरल में हुआ था, उनके पिता सिविल सर्जन थे। चेन्नई के जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने कुछ समय तक जमशेदपुर स्थित टिस्को में काम किया, बाद में डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें छात्रवृत्ति दी गई, जिससे उन्होंने इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग में अपना प्रशिक्षण पूरा किया। वर्ष 1948 में उन्होंने मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की, जिसमें डेयरी इंजीनियरिंग एक विषय के रूप में थी।

उन्होंने डेयरी क्षेत्र मे कई प्रकार के नये अन्वेषण और खोज कए, जिससे भारत में दूध के उत्पादन में आमूलचूल बदलाव हुआ। डेयरी क्षेत्र को विकसित करने के लिए उन्होंने भारत में ऑपरेशन फ्लड योजना का शुभारंभ किया, जिसके चलते दूध के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। कम ही समय में वर्ष 1998 में भारत ने अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने की सूची में पहला नंबर हासिल किया। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में उन्होंने लगभग 30 संस्थाओं की स्थापना की, जिसमें अमूल, जीसीएमएमएफ, आरआरएमए और एनडीडीबी जैसी संस्थाएं शामिल है। 1965 में डॉ वर्गीज कुरियन को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय दूध विकास बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया।

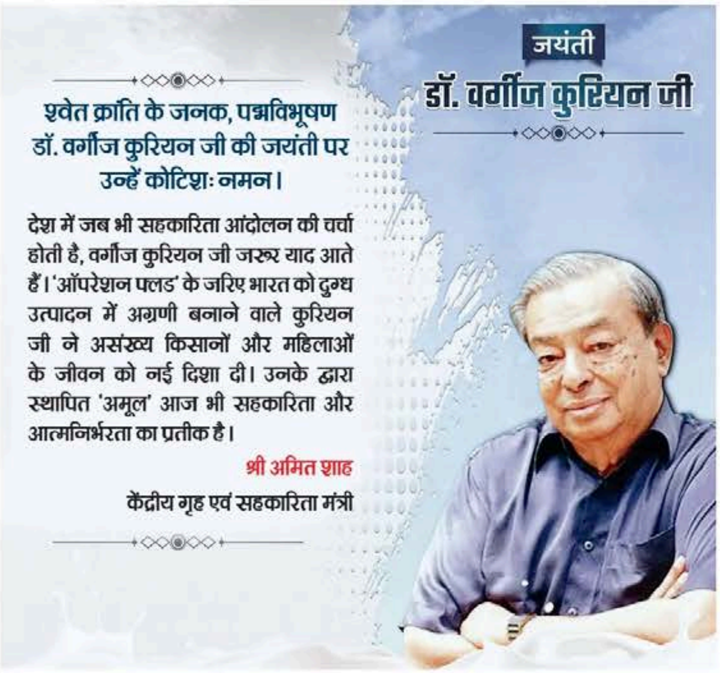

डॉ कुरियन की उपलब्धि

- वर्ष 1963 में डॉ कुरियन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया
- वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया।
- वर्ष 1966 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- वर्ष 1986 में कुरियन को कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सहित अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति पुरस्कार से सम्मानित डॉ वर्गीज कुरियन का 9 सितंबर 2012 को 90 वर्ष की आयु में गुजरात में देहांत हो गया। उनकी जयंती पर भारत में हर साल 26 नवंबर राष्ट्रीय मिल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन ने भारत में दूध उत्पादन की सबसे बड़े डेयरी सहकार अमूल की स्थापना की, कुरियन अमूल के अध्यक्ष और संस्थापक भी थे। अमूल के कार्य मॉडल और पैटर्न के आधार पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी बनाया गया। इसी के तहत वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड लांच किया गया, जिसे दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।■

डॉ. उदय शंकर अवस्थी को मिला सहकारिता का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय अवार्ड

सहकार उदय टीम

भारत की सर्वोच्च उर्वरक सहकार के प्रबंधन निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी को विश्व सहकारिता का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) द्वारा डॉ. अवस्थी को वैश्विक सहकारिता सम्मेलन में रोशडेल पायनियर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉ अवस्थी यह अवार्ड पाने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति हैं, इससे पहले श्वेत क्रांति के जनक डॉ वर्गीज कुरियन को यह अवार्ड वर्ष 2001 में दिया गया था। रोशडेल पायनियर्स अवार्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (आईसीए) द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवार्ड की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इसका उद्देश्य एक ऐसे व्यक्ति या विशेषज्ञ परिस्थितयों में काम करने वाले सहकारी संगठन को मान्यता देना है, जिसने नवीन एवं वित्तीय रूप से टिकाऊ सहकारी गतिविधियों में योगदान दिया हो व जिससे उनके सदस्यों को काफी लाभ हुआ हो। आईसीए द्वारा यह अवार्ड वैश्विक सहकारिता सम्मेलन में भारत मंडपम के मंच पर दिया गया।

सहकारिता मंत्रालय, इफको लिमिटेड और आईसीए की संयुक्त साझेदारी में आयोजित वैश्विक सहकारिता सम्मेलन में आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को द्वारा डॉ. अवस्थी को यह अवार्ड दिया गया। वर्ष 1976 में डॉ यूएस अवस्थी इफको में कैमिकल इंजीनियर के तौर नियुक्त किए गए थे। इस दौरान उर्वरक सहकार ने अपनी उत्पादन क्षमता में 292 प्रतिशत और शुद्ध संपत्ति में 688 प्रतिशत की वृद्धि की। डॉ. उदय शंकर अवस्थी के नेतृत्व में इफको ने कई तरह की व्यवसायिक गतिविधियों में भी कदम रखा, इसके साथ स्वदेशी नैनो उर्वरक को विकसित किया गया। अवार्ड ग्रहण करने के बाद इफको के एमडी डॉ उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि मैं इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहकारी से समृद्धि के दृष्टिकोण का प्रतीक है, इसके साथ ही यह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इफको के असाधरण प्रयासों को भी उजागर करता है। डॉ अवस्थी ने कहा कि इफको ने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया (तरल) जैसे नैनो उर्वरकों के माध्यम से टिकाऊ कृषि का समर्थन किया है तथा कृषि पद्धतियों में बदलाव तथा पर्यावरण अनुकूल समाधानों को पूरा किया है। नैनो यूरिया के माध्यम से भारत की उर्वरक आयात निर्भरता कम हुई है और भारी पैकेजिंग की जगह अब उर्वरकों की पैकिंग बोतलों में होती है। नैनो उर्वरक से मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, किसानों की लाभप्रदता को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी नैनो यूरिया का प्रयोग कारगर साबित हुआ है। अधिकांश राज्यों के किसान अब खेतों में नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य देश भी नैनो यूरिया के लिए भारत के साथ संपर्क में हैं। भविष्य में 25 और देशों को नैनो उर्वरक को निर्यात किया जाएगा। ■

इफको की उपलब्धि

- इफको ने नैनो डीएपी तरल की 44 लाख बोतलों का उत्पादन और नैनो यूरिया की 2.06 करोड़ से अधिक बोतल बेचकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
- किसानों के बीच इसके प्रयोग के लिए इफको ने 80 हजार क्षेत्रीय प्रदर्शनी आयोजित की, 80 हजार से अधिक किसान और 1500 ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया।
- इफको का कुल उर्वरक उत्पादन 88.95 लाख टन पहुंच गया है, जिसमें 45.85 लाख टन यूरिया और 40.10 लाख टन एनपीके, डीएपी, डब्लूएसएफ और विशेष उर्वरक शामिल है।
- बीते वित्तीय वर्ष में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बिक्री कुल 112.26 लाख टन रही, जिससे जैविक और रासायनिक उर्वरक के उपयोग में वृद्धि हुई।

सहकारिता सम्मेलन में पहुंचे जाने माने वैश्विक सहकारी नेता

➲ भूटान एग्रोफूड जिनलैब को मिला भारत का प्यार

सहकार उदय टीम

भारत के प्रति भूटान का अगाथ प्रेम है। भूटान के प्रधानमंत्री ने आईसीए के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में इस बात को शब्दों के माध्यम से प्रकट भी किया। छः दिवसीय आईएसए के वैश्विक सम्मेलन में भूटान सहित ईरान और मंगोलिया की सहकारी समितियां अपने उत्पाद लेकर पहुंचे हुए थे। भूटान की एग्रो सहकार जिनलैब अपने जैविक एग्रो उत्पाद के साथ भारत पहुंचे थे। जिनलैब आर्गेनिक हल्दी, लेमनग्रास ऑयल, शहद, कीवी चटनी सहित अन्य उत्पादों में काम करती है। सहकारिता सम्मेलन के माध्यम से जिनलैब के सहकार भारत में भी अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं। इसी तरह ईरान और मंगोलिया के कलाकारों ने भी अपनी सहकारी समितियों के उत्पादों को प्रदर्शित किया।

जिनलैब के सीईओ कल्याण माहत ने बताया कि भूटान के एग्रो सहकार के माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित वैश्विक सहकार सम्मेलन में अपने उत्पाद के साथ शामिल होने के लिए पहुंचे माहा ने बताया कि अभी हम भारत में एक अच्छा उपभोक्ता समूह तैयार कर चुके हैं, मुंबई से लेकर पूणे तक हमारे उत्पादों को बेचा जा रहा है। सहकारिता सम्मेलन के माध्यम से माहा अपने कारोबार का विस्तार देश में करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि यहां हमें बहुत प्यार मिला है, बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) के माध्यम से दोनों देशों के बीच के रिश्ते और भी मजबूत होगें।

गुलबहार की अनूठी हस्तनिर्मित कलाकृति

कोऑपरेटिव हॉट में ईरान की एक महिला से भी मुलाकात हुई, जो कपड़ो की कतरनों से बेहद सुंदर कलाकृतियां बनाती हैं। गुलबहार हयाती को कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके है। हयाती यूं तो कई सालों से अपनी हाथ की बनाई कलाकृतियों के जरिए लोगों के दिलों में राज कर रही थी, लेकिन वर्ष 2015 में उन्होंने अपने काम को बढ़ाने के लिए सहकारिता का गठन किया। इनके हस्तनिर्मित गलीचे और कलाकृतियों की कीमत पांच हजार से दस हजार रुपए तक है। गुलबहार ने बताया कि भारत में उनकी कलाकृतियों को काफी सराहना मिली है, वैश्विक सहकारिता सम्मेलन में आने से उन्हें बहुत खुशी हुई है, गुलबहार ने बताया कि यदि सहकारिता के

क्षेत्र में दो देशों के बीच साझेदारी बढ़े, तो निश्चित रूप से यह सभी के लिए बेहतर होगा। गुलबहार की कलाकारी को अंतराराष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। गुलबहार ने बताया कि एक कलाकृति को पूरा करने में छह महीने से अधिक का समय लग जाता है, महीन कलाकारी और काम की सफाई की वजह से इन कलाकृतियों की कीमत अधिक होती है।

मंगोलिया का जूट भी आया पसंद

मंगोलिया वुलेन हस्तनिर्मित स्टॉल पर भी लोगों ने काफी रूचि दिखाई। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मंगोलियन एग्रीकल्चर मूल रूप से जूट और कपास से बने उत्पाद बनाती है, जिनका वुलेन काफी गर्म होता है। वैश्विक सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय सहकारी समितियों की भागीदारी से सहकार का दायरा बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कारोबारी साझेदारी बेहतर होगी। आईसीए के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया गया। मंगोलिया से स्टॉल लगाने आई महिला बेतामिन ने बताया कि जूट के इस काम में अधिकांश महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, हस्तनिर्मित वुलेन वर्क को अंतररष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए इसे सहकरिता मॉडल पर उतारा गया। इससे कारीगरों को विस्तृत बाजार उपलब्ध होता है, उनकी कला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसके साथ ही कारीगरों की आजीविका में भी सुधार होता है।

सेवा सहकार से स्वावलंबी हो रहीं महिलाएं

वैश्विक सहकारिता सम्मेलन में गुजरात के सेवा सहकार की महिलाओं ने भी अपना स्टॉल लगाया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी कला को विस्तृत बाजार देने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सेवा सहकार लंबे समय से काम कर रही है। हस्तनिर्मित कलाकृतियों को सेवा सहकार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। सेवा सहकार की महिलाओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को फैब इंडिया और खादी ग्रामोद्योग के स्टोर पर भी पहुंचाया जाता है।

वर्ष 1992 में सेवा (गुजरात स्टेट वुमेन्स सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड) की स्थापना की गई। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सेवा सहकार का गठन किया गया। बीते 27 साल में सेवा से तीन लाख से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो लगभग 100 प्राथमिक सहकारी सोसाइटी के माध्यम से कारोबार कर रही हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सेवा सहकार का लगभग 300 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर रहा। सेवा फेडरेशन, सेवा कलाकृति, सेवा रिहैब आदि के माध्यम से महिलाओं को रोजगार सृजन कर रही है। एप्रेन, सजावटी समान, जूट के डिजाइर वाल हैंगिंग, बैग, डोरमेट, पैचवर्क आदि महिलाओं द्वारा निर्मित सामान को स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाता है। सेवा सहकार की दिल्ली पहुंची कोऑर्डिनेटर मधु सूद ने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को विस्तृत बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यशालाओं के माध्यम से हुनर भी सिखाया जाता है, जिससे वह अपने उत्पादों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना सकें। वर्कशाप और लाइव डेमोन्सट्रेशन के माध्यम से महिलाओं की बाजार तक सीधे पहुंच बनती है, जिससे वह अपने उत्पादों का सही मूल्य प्राप्त कर पाती है, इससे बिचौलियों को जाने वाला पैसा बच जाता है। सेवा सहकार से जुड़ी महिलाओं द्वारा डिजाइन की गई ब्लॉक प्रिंटिंग साड़ी, एंब्रोयडरी और पैचवर्क आज एक अलग पहचान बना चुकी है। सेवा सहकार से जुड़ी महिलाओं को कारीगरी का प्रमाणपत्र मिलने से यह आसानी से अपने उत्पादों को हुनर हाट हस्तशिल्प मेले में बेच पाती हैं। स्टॉल पर मौजूद ऐसी ही एक कारीगर सुमन ने बताया कि वह बीते दस साल से सेवा से जुड़ी हैं। पहले वह आजीविका के लिए आसपास के लोगों के कपड़े सीलती थीं, लेकिन सेवा सहकार से जुड़ने के बाद उन्हें अधिक काम और अधिक पैसे मिलने लगे, अब उनका जीवन अच्छा गुजर रहा है।■

भारतीय सहकारिता के लिए गर्व का क्षण

ग्लोबल कोआपरेटिव कॉन्फ्रेस आयोजन समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार शुक्ला, आईसीए के अध्यक्ष एरियल ग्वार्को, भूटान के प्रधानमंत्री एवं इफको अध्यक्ष दिलीप संघाणी।

दिलीप संघाणी

सहकारिता की भावना उन्मुक्त रूप से बहती है, इसका कोई किनारा नहीं है। जहां से भी यह गुजरती है, वहां छोटे-बड़े पैमाने पर विकास या वित्तीय सहाय का बीजारोपण करती जाती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सहकारिता एक शब्द से ज्यादा सामाजिक उत्थान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि इसमें, कहीं न कहीं... हम सब सम्मिलित हैं... समाविष्ट हैं... सहयोगी हैं।

रियासत को मजबूत करने के सरदार वल्लभभाई पटेल के कर्तव्यनिष्ठ प्रयास में राजाओं का विश्वास और गांधीजी के भारत छोड़ो आह्वान को जनता का समर्थन भी सामाजिक सहयोग है, इसलिए कहा जा सकता है कि सहकार जन्मजात है।

भारत की सहकारी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसकी जड़ें और संस्कृति आर्थिक व्यवस्था में निहित हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, गांवों की वित्तीय संरचना एक सहकारी संरचना का प्रतिनिधित्व करती है, रोजगार प्रदान करती है, पारिवारिक और सामाजिक विकास में भूमिका निभाती है। भारत सरकार ने सहकारिता नीति को जनहितकारी बनाने और इस गतिविधि को जन-जन तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया है। आजादी के बाद देश में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के नेतृत्व में नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इसका प्रतिबिंब अनुभवी सहकारिता श्री अमित शाह केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्री के रूप में यह मंत्रालय संभाल रहे हैं। नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद, देश के सहकारी ढांचे में 'सहकार से समृद्धि' के आदर्श वाक्य के साथ विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। हम सब इसके साक्षी हैं।

जुलाई 2024 में, मैंने भारत के सहकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित आईसीए (अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन) बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अपने संबोधन में, मैंने इफको के मेजबान के रूप में भारत में आईसीए के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित करने का निमंत्रण दिया। जिसे आईसीए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है।

132 साल पहले स्थापित, आईसीए का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 107 देशों के सहकारी नेताओं की उपस्थिति में इफको की मेजबानी में भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऐसे समय में सहयोग की विभिन्न सक्रिय जिम्मेदारियों के बीच भारत द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की व्यवस्थाओं और जिम्मेदारियों को संभालने का अवसर मिलना मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण है।

चेयरमैन, इफको व एनसीयूआई

ऋषिराज सिसौदिया

भारतीय सहकारिता को मिली वैश्विक सराहना

देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में 25 से 30 नवंबर के बीच वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस अवसर पर वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए जाने की औपचारिक घोषणा भी की गई, जिसे यादगार बनाने के लिए डाक टिकट भी जारी किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता ने बहुत कम समय में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आईसीए यानि अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के सहयोग से इफको (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड) के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन से भारतीय सहकारिता विश्व भर में गूंजायमान हो गई है।

सहकारिता मंत्रालय के समर्थन तथा 17 अन्य भारतीय सहकारी महासंघों की सह मेजबानी में आयोजित किए गए इस सम्मेलन के लिए इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने पिछले साल ब्रुसेल्स में न्यौता दिया था, जिसे सहर्ष स्वीकार किया गया। आईसीए अध्यक्ष एरियल ग्वार्को और महानिदेशक जेरोन डगलस ने अनेक देशों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर आयोजन को सफल बनाने के लिए विमर्श किया। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री दिलीप भाई संघाणी जो इफको के भी अध्यक्ष हैं, द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए।

19 अगस्त 1895 को आईसीए की स्थापना हुई। 130 साल के इतिहास में पहली बार वैश्विक सम्मेलन के लिए भारत को चुना गया। लंदन में आईसीए की पहली विश्व कांग्रेस वर्ष 1895 में हुई थी, पहली कांग्रेस के बाद अन्य देशों में तो यह आयोजन हर दो-चार साल बाद होता रहा। परंतु भारत में इसका आयोजन पहली बार किया गया। इससे पूर्व वर्ष 2023 में फिलिपिंस में वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

आईसीए सहकारी क्षेत्र का शीर्ष वैश्विक संगठन है, जिसने दो विश्व युद्ध की विभिषिकाओं के बाद भी सहकारी विचारधारा और अस्तित्व को न केवल जिंदा रखा, बल्कि दिन पर दिन इसे मजबूत भी किया। भारत स्थापना काल से ही आईसीए के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। वर्ष 1960 में भारत ने नई दिल्ली के प्रमुख स्थान पर आईसीए एशिया और प्रशांत क्षेत्र को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना के लिए स्थान दिया। लगभग बीते 64 सालों से भारत में आईसीए एशिया प्रशांत क्षेत्र कार्यालय कार्यरत है। केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और देश के पहले सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सहकारिता में भारत का डंका विश्वभर में गूंजा। सहकारिता के सिद्धांतों में सबका विकास निहित है, इसलिए सहकारिता की विचारधारा में सबके समान अस्तित्व को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। सही मायने मे सहकारिता लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक मजबूत करती है। विश्व सहकारी समुदाय की निगाह भारत की उन सहकारी उपलब्धियों पर है जो जिसे पिछले कुछ समय में हासिल की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र की 54 प्रमुख पहलें, जिसमें बहुराज्य सहकारी समिति 2023 (संशोधित), मॉडल बायलॉज, जिसमें पैक्स कंप्यूटरीकरण तथा पैक्स को विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल करना आदि ऐसे प्रयास हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर मजबूत हुए हैं। इसी के साथ तीन बहुराज्यीय सहकारी समितियां बनने से सहकारिता की विश्व पटल पर पहचान मजबूत हुई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सितंबर 2024 को सहकारिता मंत्रालय की तीन साल की रिपोर्ट प्रस्तुत की। ग्राम पंचायतों में सहकारी संस्थाओं के गठन का प्रावधान, श्वेत क्रांति और सहकारिता आदि प्रयासों के माध्यम से सहकारिता में सहकारिता को शामिल किया गया।

श्वेत क्रांति प्रथम ने विश्व को पोषण आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और वैश्विक कृषि आदान उपलब्ध कराने का मार्ग दिखाया, जिससे सहकारिता में लोकतांत्रिक ढांचा और मजबूत होगा। श्वेत क्रांति 0.2 से रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। भारत में डेयरी सहकारिता की बागडोर महिलाओं के हाथ में हैं, पशुपालन और दुग्ध सहकार में भारत की उपलब्धि अब वैश्विक हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आगाज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया गया, इसका भी विश्वभर में एक बड़ा संदेश गया है। आगामी वर्ष सहकारिता को उन्नत करने के प्रयासों से भरा होगा, जिसमें सहकारिता को एक नया आयाम मिलेगा। विभिन्न ऐसे क्षेत्र जहां अभी सहकारिता का प्रयोग नहीं हो पाया है, वहां सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में युवाओं को अधिक से अधिक सहकारी समितियों को भागीदार बनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सहकारिता में महिलाओं की भूमिका को मजबूत किया जाएगा। कुल मिला कर वर्ष 2024 के अंतिम महीने दिसंबर में हम जिस सहकारिता की बात कर रहे हैं, वर्ष 2025 के अंत तक वह सहकारिता बिल्कुल एक नये कलेवर में और अधिक मजबूती के साथ विश्वभर में अपनी पहचान बना चुकी होगी, जिससे भारतीय सहकारिता की निश्चित रूप से अहम भूमिका होगी।■

लेखक इफको के निदेशक और सहकार भारती मध्यप्रदेश के पदाधिकारी हैं

स्पेनिश दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ स्पेन की सामाजिक अर्थव्यवस्था की राज्य सचिव सुश्री मारिया एम्पारो मेरिनो सेगोविया ने केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री मुरलीधर मोहोल से मुलाकात की। सभी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की विभिन्न पहलों के जरिए महिलाओं व कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने में की सराहना की।

इफको कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और इफको अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने सभी इफको कर्मचारियों, अधिकारियों की ओर से आईसीए द्वारा रोशडेल पायनियर्स अवार्ड 2024 दिए जाने पर डॉ. उदय शंकर अवस्थी को सामूहिक बधाई दी। डॉ. अवस्थी ने कर्मचारियों द्वारा दिए गए इस सम्मान का धन्यवाद दिया और कहा कि इफको के लिए यह गर्व का विषय है।

केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर ने बिहार के जिले कटिहार में 'स्वयं सहायता समूह' की महिलाएं से भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। ये महिलाएं विभिन्न कुटीर उद्योगों से जुड़े कौशल सीख कर स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपनी उद्यमिता से देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान कर रही हैं।

फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएआई द्वारा नई दिल्ली में सस्टेनेबल फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर थीम पर वार्षिक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी सहित उर्वरक उद्योग के 2000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर नैनो यूरिया की भी जानकारी दी गई।

एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत प्रदर्शनी में इफको के स्टॉल पर संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक श्री आशुतोष मिश्रा। स्टॉल पर पहुंचे सभी किसानों को नैनो उर्वरकों तथा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग पर जानकारी प्रदान की गई। एग्रोटेक इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया।

26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों एवं उद्देशिका का स्मरण कराते हुए राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई।

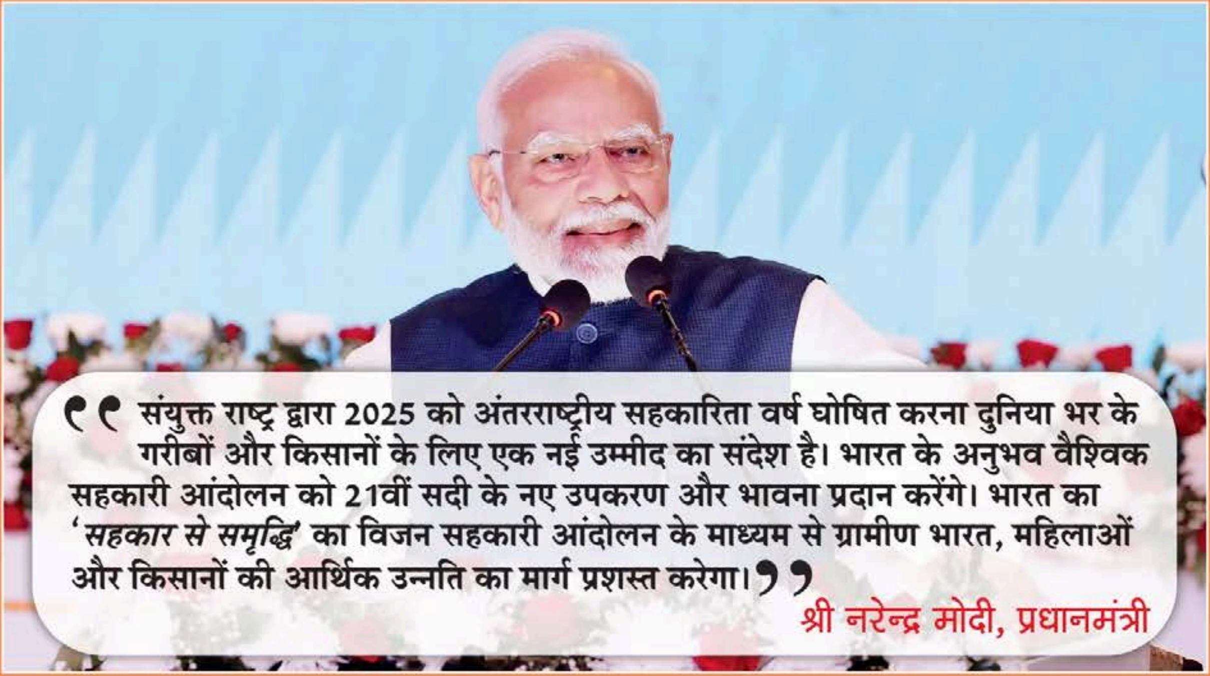

Published on 26 of every month "Sahkar Uday"

RNI No. DELHIN/2024/88557
Postal Registration No.: DL(S)-17/3560/2024-26

Posting date : 26-31 Every Month
Posted at : Lodhi Road HO, New Delhi-110003